राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 291

# प्रगति

## समाचार पत्र

अगस्त 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

## एनआईआरडीपीआर द्वारा उत्पादकता संग्रह शासन और प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियों का संस्थानीकरण

3 एनआईआरडीपीआर द्वारा उत्पादकता संग्रह शासन और प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियों का संस्थानीकरण

# विषय-सूची


6
एनआईआरडीपीआर में पीजीडीआरडीएम स्नातकों का 16 वां दीक्षांत समारोह आयोजित

7
ग्राम पंचायत में विकेंद्रीकृत योजना: चेनुष्ठ ग्राम पंचायत का मामला अध्ययन

8
डीडीयू-जीकेवाई कक्ष, एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित एसआरएलएम के सीईओ और सीओओ की संगोष्ठी

10
संकट संचार और मीडिया प्रशिक्षण पर सीडीसी ने किया कार्यशाला का आयोजन

11
डॉ. सुरेश बाबू, आईएफपीआरआई ने भारतीय कृषि में ग्रामीण विकास की चुनौतियों पर प्रस्तुत किया व्याख्यान

12
एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित

13
जे-पाल के सहयोग से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण कार्यशाला

14
मोबाइल फिल्म निर्माण पर तीन दिवसीय कार्यशाला ने प्रशस्त किया नवोदित फिल्म निर्माताओं के लिए विकल्पों का मार्ग

15
आईसीटी अनुप्रयोग और ई-शासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

*किसानों के लिए और किसानों द्वारा- एफपीओ की वार्षिक आम सभा*

# एनआईआरडीपीआर द्वारा उत्पादकता संग्रह शासन और प्रबंधन में श्रेष्ठ पद्धतियों का संस्थानीकरण

किसानों के जीवन स्तर में सुधार के लिए संस्थागत सामूहिक मॉडल के रूप में सहकारी समितियों का विकास एक शताब्दी पुराना विचार है । पहले से ही ऋण, उत्पादन और विपणन जोखिमों से जूझ रहे किसानों की सौदेबाजी की क्षमता पर छोटे भूमि जोत स्वामित्व का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । सहकारी समितियों पर भारी निवेश के बावजूद, केवल कुछ ही व्यवहार्य और सफल उद्यम के रूप में उभरे हैं, जिन्होंने कई असफलताओं के बावजूद कुछ सहकारी समितियों की सफलता के कारणों को खोजने के लिए खोज की है । 'उपजाऊ भूमि' का तर्क है कि उत्तरी गुजरात और पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठा, परिश्रमी और उद्यमी पाटीदार गुजरात में डेयरी सहकारी समितियों और पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ना सहकारी समितियों की सफलता के कारण हैं । हालांकि, इसने उद्यमीकर्ताओं को कोई सांत्वना नहीं दी है क्योंकि तटीय आंध्र प्रदेश या पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच सहयोग के पैटर्न को फिर से नहीं बनाया गया है जो समान रूप से परिश्रमी और उद्यमशील हैं । कुछ सहकारी समितियों की सफलता के लिए अध्ययनों से एक और अनिवार्य व्याख्या सामने आई है जो नियंत्रण के बाहरी नियंत्रण को नियंत्रित करने और उदार कानूनी और नीतिगत ढांचे को सक्षम करने पर आधारित है । सहकारी समितियों को नौकरशाही और राजनीतिक संबंधों के चुंगल से मुक्त करने के बेहतर तरीके की खोज में, उत्पादकर्ता कंपनी कानून 2003के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अध्याय IX ए के रूप में लागू हुआ, जिसमें ज्यादातर उदार सहकारिता समिति अधिनियम के सिद्धान्त के साथ लेकिन एक कॉर्पोरेट समर्थन के साथ शामिल था । लगभग 6000 एफपीओ देश में प्रमुख रूप से निर्माता कंपनी प्रारूप में और कुछ राज्यों में उदार सहकारी प्रारूप के तहत पंजीकृत किए गए ।

**एग्रिबिजिनेस का क्षेत्र आगामी पांच वर्षों में एफपीओ के रूप में 25,000 से अधिक उत्पादकर्ता संग्रह तैयार होने जा रहा है । प्रबंधन और शासन में सर्वोत्तम पद्धतियों को संस्थागत करना इन एफपीओ को व्यवसाय में बने रहने के लिए समय की मांग है**

**केंद्रीय बजट 2018-19 और 2019-20: एफपीओ पर ध्यान केन्द्रित करना**

किसान संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने लगातार दो बजटों में निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है ।

- सब्जियों के मूल्य में संवर्धन, प्रसंस्करण और फसल प्रबंधन के लिए एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए " ऑपरेशन फ्लड" के अनुरूप प्याज, टमाटर और आलू की फसलों के लिए 500 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ " ऑपरेशन ग्रीन्स" का शुभारंभ ।
- 2018-19 से शुरू पाँच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये तक के एफपीओ के लिए 100 प्रतिशत की कर कटौती ।
- अर्थव्यवस्था पैमाने को सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच वर्षों में नई 10,000 एफपीओ को बढ़ावा देना ।

एक किसान उत्पादकर्ता संगठन के सदस्य

**एफपीओ की वर्तमान स्थिति**

पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश कुछ राज्य हैं जो एफपीओ के प्रचार प्रसार में अग्रणी हैं । जबकि कुछ निधिकरण एजेंसियां एफपीओ को सहकारी पंजीकरण के साथ बढ़ावा दे रही हैं, अन्य लोग कंपनियों के अधिनियम के तहत पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं । जब 1990 में केंद्र सरकार ने ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशों के अनुसार देश में सहकारी कानून को उदार बनाया है, तो नौ राज्यों ने अपनी सहकारी समितियों को उदार बनाने के लिए सिफारिशों को अपनाया है ।

एपी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने अपने सहकारी कानून जैसे को उदार बनाया है वे सहकारी एफपीओ को प्रोत्साहित कर रहे हैं । उदाहरण के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए सोसायटी (एसईआरपी) आन्ध्रप्रदेश ने परस्पर सहायता सहकारी समिति (एमएसीएस) अधिनियम के तहत अब तक 169 एफपीओएस पंजीकृत किए हैं। एफपीओ के पंजीकरण के संबंध में कुछ अन्य राज्यों में भिन्नता देखी गई । भारतीय कंपनी अधिनियम को अभी तक सिक्किम की राज्य सरकार द्वारा नहीं अपनाया गया । इसलिए, इस राज्य में एफपीओ सिक्किम राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं । पश्चिम बंगाल ने कंपनी संशोधन अधिनियम, 2002 की अनुमति नहीं दी है । इसलिए नाबार्ड और एसएफएसी दोनों द्वारा प्रवर्तित एफपीओ ट्रस्ट अधिनियम के तहत इस राज्य में पंजीकृत हैं । हालाँकि, एफपीओ जो ट्रस्ट और समिति के तहत पंजीकृत थे गैर-लाभकारी संस्थाएं होने के कारण व्यापार करने में सीमितता पाई गई और इसलिए वे कंपनियों में बदल रहे हैं । व्यवसाय में उत्पन्न अधिशेष आय को व्यवसाय के संचालन के लिए साझा नहीं किया जा सकता है और लाभ को साझा करने के लिए, कंपनी या सहकारी समिति के रूप में एक वाणिज्यिक संस्था को देश में पंजीकृत अधिकांश एफपीओ द्वारा पसंद किया गया है ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई- एनआरएलएम) के विभिन्न हस्तक्षेपों के तहत 86,000 से अधिक उत्पादक समूहों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) , एमकेएसपी वार्षिक कार्य योजना, एसआरएलएम वार्षिक कार्य योजना, और विश्व बैंक समर्पित निधि । ये उत्पादक समूह छोटे आकार के हैं; अपंजीकृत एसएचजी मुख्य रूप से मितव्यय और ऋण गतिविधियों के लिए गठित किए गए हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उन फसलों की सामूहिक मूल्य श्रृंखला और विपणन गतिविधियों को संभालें जो वे संभाल रहे हैं । डीएवाई-एनआरएलएम बड़े पैमाने पर सदस्य स्वामित्व वाले शासित निर्माता उद्यमों (पीई) को बढ़ावा दे रहा है, जिसे या तो निर्माता कंपनियों या सहकारी समितियों या उदार सहकारिता समिति अधिनियम (एपी और तेलंगाना में पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहकारी समिति अधिनियम) के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है । आज तक लगभग 131 महिला केंद्रित एफपीसी डीएवाई- एनआरएलएम के तहत पंजीकृत हैं ।

हालांकि, बाजार संबंधों को बनाने के लिए सामूहिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई उत्सुकता धीरे-धीरे दूर हो रही है क्योंकि निर्माता कंपनियां चौराहे पर हैं, यहां क्या करना है और यहां से कहां जाना है के बड़े सवाल का सामना करना पड़ रहा है । एफपीओ पर कई अध्ययनों के निष्कर्ष जिनमें सीएएस, एनआईआरडीपीआर शामिल हैं, यह दर्शाता है कि एक सही किसान हितैषी नीति के बिना और एफपीओ की निरंतर निगरानी और क्षमता निर्माण के लिए प्रक्रियाएं, उन्हें महत्वाकांक्षी "कृषि आय की दोहरीकरण" पहल के साथ संरेखित करना संभव नहीं है ।

इस संदर्भ में, नाबार्ड, आंध्र प्रदेश के लिए एफपीओ के संसाधन समर्थन एजेंसी (आरएसए) के रूप में एनआईआरडीपीआर का सीएएस, एफपीओ के प्रबंधन और शासन में निम्नलिखित सर्वोत्तम पद्धतियों को संस्थागत कर रहा है ।

- **किसान सदस्यों का ऑनलाइन और गतिशील डेटाबेस संग्रह**

किसान सदस्यों की फसल की आवश्यकताओं पर गतिशील जानकारी का प्रसार उनके लिए सही समर्थन पद्धति तैयार करने में मदद करता है जैसे इनपुट आपूर्ति, स्थानीय केवीके और आरएआरएस से प्रौद्योगिकी सहायता की सुविधा के अलावा उच्च लागत मशीनरी का कस्टम हायरिंग । ओपन डाटा किट (ओडीके) प्लेटफ़ॉर्म पर एफपीओ के निदेशक मंडल और सीईओ को प्रशिक्षण दिया गया, जो बदले में किसानों का डाटा एकत्र कर रहे हैं और इसे एनआईआरडीपीआर के ओडीके सर्वर

पर अपलोड कर रहे हैं । यह मूल्य चैन और व्यापार योजना विकास पर सूक्ष्म नियोजन के लिए एफपीओ के डाटा के त्वरित सारणीकरण में मदद करता है । डाटा को किसान सदस्य से एकत्र किया गया है, जो सदस्य सदस्यता शुल्क के साथ शामिल हुए हैं या जिन्होंने इक्विटी का भुगतान किया है । इसलिए, यह प्रणाली उक्त को समाप्त कर रही है) i) उत्पादक संगठन प्रचार संस्थान (पीओपीएल) द्वारा एक से अधिक एफपीओ में शेयर धारक किसान सदस्यों की दोहरी रिपोर्टिंग और ii) पीओपीएल द्वारा एक एफपीओ के दौरान किसान सदस्यों की रिपोर्टिंग ।

- **संवैधानिक और परिचालन अनुपालन कैलेंडर**

समय पर वैधानिक और परिचालन का अनुपालन न करने के कारण कई अच्छे प्रदर्शन करने वाले एफपीओ ने चूक क्षेत्र में प्रवेश किया है । निदेशक मंडल द्वारा भुगतान की जाने वाली भारी दंड एफपीओ को बंद होने की दिशा में अग्रसर करती है । सीएएस द्वारा तैयार एक अनुपालन कैलेंडर आंध्र प्रदेश के सभी एफपीओ को ईमानदारी से पालन करने के लिए परिचालित किया गया ।

- **एफआईजी आधारित सूक्ष्म योजना दृष्टिकोण के सिद्धान्त का समर्थन करना**

किसान हित समूह (एफआईजी) एक एफपीओ तक अंतिम उत्पादक तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करेगा । इसके अलावा, राज्य कृषि और लाइन विभागों की कई योजनाएं एफआईजी के लिए उपयुक्त हैं । एफपीओ में मिलाए गए एसएचजी के पंचसूत्र के सिद्धांतों के बाद किसान हित समूहों का एक नेटवर्क एफपीओ के प्रबंधन के लिए आदर्श प्रवेश द्वार है ।

- **राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थाओं के साथ अभिसरण**

भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, भारतीय चावल अनुसंधान, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड जैसे राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से क्षेत्र विशिष्ट एफपीओ को मजबूत करने में मदद मिली । एनआरईटीपी (राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रुपांतरण कार्यक्रम ) के तहत कई एनआरएलएम एसएचजी संघ के निर्माता कलेक्टिव में मेटामॉर्फोसाइज्ड हो रहे हैं और पहले से ही 150 ऐसे कलेक्टिव एनआरएलएम - दीन दयाल अंत्योदय योजना के बैनर तले बन रहे हैं । नाबार्ड के सदस्य एफपीओ को महिला एसएचजी के साथ तालमेल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे विभिन्न वस्तुओं के मूल्य श्रृंखला विकास के परिपूरक बन सके । केवीके और आरएआरएस जैसे स्थानीय संस्थानों के सहयोग से इन संस्थाओं की तकनीकी ताकत का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

- **कार्यनिष्पादन के लिए संकेतक विकसित करने वाली समवर्ती निगरानी पद्धति**

एफपीओ निष्पादन संकेतक विकसित किए गए और एक साल के रोड मैप और रणनीतिक व्यापार योजना की तैयारी के लिए इन टेम्पलेट्स पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । इन पद्धतियों से एफपीओ को एक स्थायी पथ पर बने रहने में मदद मिलेगी, जो असमान है ।

- **शासन की प्रभाविता सुनिश्चित करना**

प्रशासन की गुणवत्ता एफपीओ के विस्तृत कार्यों के लिए समितियों के साथ आंतरिक लोकतंत्रीकरण पर निर्भर करती है । इसके अलावा, केवल समितियों के संविधान का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि वे उन सेवाओं का वितरण और कार्यों का निर्वाह न करें, जिनके लिए उनका गठन किया गया है । समिति के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों, कार्य योजना और रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में अद्यतन किया जा रहा है ताकि एफपीओ के सीईओ समितियों के काम को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित कर सकें ।

अगर यह वास्तव में संघर्षों और वैधानिक दंड के लिए गुंजाइश दिए बिना शेयरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा कर पेशेवर रूप से विकसित होना चाहता है तो अद्यतन बुक कीपिंग किसी भी एफपीओ के लिए गैर-परक्राम्य है । हालांकि एसएचजी के पास बुक कीपिंग की पद्धति है, लेकिन देश में अब तक एफपीओ के लिए खातों की मानक पुस्तकें नहीं हैं । बुक कीपिंग में अपराध के मुद्दे को हल करने के लिए, एनआईआरडीपीआर के सीएएस ने खातों की विभिन्न पुस्तकों के लिए प्रारूप तैयार किया हैं और बुक कीपिंग पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ को प्रशिक्षित किया गया है ।

**डॉ. सी.एच. राधिका रानी**
एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष
कृषि अध्ययन केंद्र
कवर पेज डिजाइन: **श्री वी.जी. भट्ट**

एफपीओ की बैठक प्रगति पर है

# एनआईआरडीपीआर में पीजीडीआरडीएम स्नातकों का 16 वां दीक्षांत समारोह आयोजित

श्रीमती नीला गंगाधरन, पूर्व मुख्य सचिव, केरल सरकार (पहली पंक्ति, बाएं से 4 थें), डॉ. डब्ल्यु. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से 5 वें), डॉ. प्रकाशम टाटा, कार्यकारी निदेशक, अपशिष्ट प्रौद्योगिकी परिवर्तन केंद्र, ग्रेटर शिकागो (पहली पंक्ति, दाईं ओर से 5 वें), श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, दाईं ओर से 4 थें) और डॉ. फ्रैंकलिन लल्तिखुंमा, रजिस्ट्रार (पहली पंक्ति, बाएं से दूसरे) अन्य गणमान्य लोगों और छात्रों के साथ दीक्षांत समारोह में ।

पीजीडीआरडीएम पाठ्यक्रम स्नातकों का 16 वां दीक्षांत समारोह 9 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में आयोजित किया गया । केरल सरकार के पूर्व मुख्य सचिव नीला गंगाधरन ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए ।

श्रोताओं को संबोधित करते हुए, श्रीमती नीला गंगाधरन ने कहा कि ग्रामीण विकास पेशेवरों का एक पूल बनाया जाना चाहिए, जो ग्रामीण गरीबों के उत्थान में मदद करेंगे और देश में ग्रामीण विकास की पहल को आगे बढ़ाएंगे । डॉ. प्रकाशम टाटा, कार्यपालक निदेशक, अपशिष्ट प्रौद्योगिकी परिवर्तन केंद्र, ग्रेटर शिकागो सम्मानीय अतिथि थे । समारोह की अध्यक्षता एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने की । उन्होंने समग्र रूप से और विशेष रूप से भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संस्थान के योगदान के बारे में विस्तार से बताया ।

उन्होंने कहा कि एनआईआरडीपीआर से करीब 730 ग्रामीण विकास पेशेवरों ने स्नातक किया है और वे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एमजीएनआरईजीएस आदि सहित देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए पेशेवर योगदान दे रहे हैं । संस्थान के छात्र दूरदराज के गांवों को कवर करने के लिए निम्न स्तर पर काम करते हैं ।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक ने छात्रों के प्रदर्शन और ग्रामीण समाज के उत्थान में उनकी भूमिका की बात की । उन्होंने जोर दिया कि उन्हें परिवर्तन प्रबंधक बनने के लिए क्षेत्र के प्रति जोश विकसित करना चाहिए ।

पीजीडीआरडीएम ( ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा) (बैच -1 6 ) के दीक्षांत समारोह में कुल 28 छात्रों ने अपने प्रमाण पत्र प्राप्त किए । सर्वश्रेष्ठ छात्र का स्वर्ण पदक अमर्त्य कृष्णा रॉय को दिया गया । रजत और कांस्य और डीजी के विशेष पदक क्रमशः उल्लीगड्डा वीरेशम, सहारा बिसोई और पेनिओनी कुइनिकोरो (फिजी से) को दिए गए ।

पीजीडीआरडीएम के १६ वें बैच के छात्र शपथ लेते हुए; (अंदर) डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर शपथ दिलाते हुए; (दाएं) मुख्य अतिथि व गणमान्य व्यक्ति दीप प्रज्जवलित करते हुए

# ग्राम पंचायत में विकेंद्रीकृत योजना: चेनुष्ठा ग्राम पंचायत का मामला अध्ययन

चेनुष्ठा ग्राम पंचायत में चल रही ग्राम सभा

विकेंद्रीकृत योजना ग्रामीण गरीबों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने के लिए लोकतंत्रीकरण का एक विशिष्ट भाग है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढाँचा आवश्यक है जिसमें खाद्य और कृषि से संबंधित उपदान के प्रावधान के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल हैं। ग्राम पंचायतें स्थानीय सरकार की संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं जो योजनाओं को तैयार करती हैं और योजनाओं को लागू करती हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। विकेंद्रीकृत योजना विभिन्न स्थानीय योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। यह विकास प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाता है।

महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के अमरावती जिले में स्थित चेनुष्ठ ग्राम पंचायत की स्थापना 1 मई, 1962 को हुई। यह बेहतर स्वच्छता के लिए शौचालयों के निर्माण, कचरे के सुरक्षित निपटान और सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव हेतु समुदायों के सामूहिक संग्रहण के लिए कार्यक्रम शुरू करने के बाद से किया गया है। इसे 2008 में पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) से निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है।

**चेनुष्ठा ग्राम पंचायत की रूपरेखा**

चेनुष्ठा ग्राम पंचायत अमरावती जिले के टियोसा तालुका में स्थित है। यह अमरावती के जिला मुख्यालय से पूर्व की ओर 40 किमी और राज्य की राजधानी मुंबई से 688 किमी की दूरी पर स्थित है। गांव में कुल 210 परिवार निवास करते हैं, जिनमें से 57 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, गाँव की जनसंख्या 862 है, जिसमें 449 पुरुष हैं और 413 महिलाएँ हैं। 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 77 है, जो कुल जनसंख्या का 8.93 प्रतिशत है। चेनुष्ठा का औसत लिंगानुपात 920 है जो राज्य के औसत 929 से कम है। बाल लिंग अनुपात 878 है, जो महाराष्ट्र के औसत 894 से कम है।

कपास, संतरा, सोया और गेहूं इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, गाँव में साक्षरता दर 85.61 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र में यह 82.34 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता 91.18 प्रतिशत है, जबकि महिला साक्षरता दर 79.58 प्रतिशत है। भारत के संविधान और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, चेनुष्ठा गाँव का प्रशासन सरपंच (गाँव के मुखिया) द्वारा किया जाता है, जो गाँव का निर्वाचित प्रतिनिधि है। पंचायत में एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनवाड़ी केंद्र है। ग्राम पंचायत में कोई हाई स्कूल नहीं है और छात्रों को निकट स्थित हाई स्कूल तक पहुँचने के लिए ४ किमी की यात्रा करनी पड़ती है। सरकारी स्वास्थ्य उप-केंद्र और पशु अस्पताल जैसी अन्य सुविधाएं ग्राम पंचायत से 4 किमी की दूरी पर स्थित हैं।

**चेनुष्ठा ग्राम पंचायत का प्रबंधन**

चेनुष्ठा ग्राम पंचायत में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पंचायत सचिव और डाटा एंट्री ऑपरेटर, चपरासी और पानी पुरथा कर्मचारी (जल आपूर्ति पुरुष) जैसे पूर्णकालिक कर्मचारी हैं। पंचायत की बैठकों में सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया जाता है, विशेष रूप से महिलाएँ। इन बैठकों में, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है, योजनाओं की समीक्षा की जाती है और विभिन्न योजनाओं के बारे में कार्यक्रम होते हैं।

**संरचना सुविधाएं**

पंचायत के पास पानी, सफाई, बिजली, इत्यादि सुविधाओं के लिए अपनी स्वयं की इमारत है ।पंचायत कार्यालय अच्छी तरह से सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर, कंप्यूटर और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन से सुसज्जित है। पंचायत में कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था है। ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक हॉल होता है जिसका उपयोग ग्राम सभा और अन्य सार्वजनिक बैठकों के लिए किया जाता है।

**निर्णय लेने की प्रक्रिया**

पंचायत के सदस्य विभिन्न मुद्दों और विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए नियमित मासिक बैठकें करते हैं। पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों की मदद से सरपंच फैसले लेता है। मासिक बैठकों के अलावा, ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार विशेष और आपातकालीन बैठकें आयोजित करती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी योजना को लागू करने से पहले ग्रामीणों के साथ अनौपचारिक बैठकें करती है। बैठकों में, पिछले वर्ष के कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाती है, ताकि वार्षिक योजनाओं को मंजूरी दी जा सके और ग्राम सभा बैठकों में लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।

**पारदर्शिता और जवाबदेही**

ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष छह ग्राम सभाओं का आयोजन करती है। नियमित ग्राम सभा के अलावा, महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए महिला ग्राम सभा हर साल आयोजित की जाती है। २०१५-१६ में, महात्मा गांधी तांता मुक्ति गाँव मोहिम (विवाद मुक्त ग्रामीण योजना) समिति का गठन किया गया, जिसमें १३ सदस्य शामिल हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, ग्राम पंचायत सदस्य और गाँव के युवा शामिल हैं। समिति गांवों को मौजूदा विवादों की पहचान करने, उन्हें आपराधिक, सामूहिक, राजस्व और नोटिंग में वर्गीकृत करने में मदद कर रही है। ग्राम पंचायत योजना की पारदर्शिता और बेहतर जवाबदेही के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा का अभ्यास कर रही है जैसे कि मनरेगा, आईएवाई आदि।

**श्रेष्ठ पद्धतियां**

ग्राम पंचायत ने अपने विकास कार्यों में नवीन रणनीतियों का पालन और विकास किया है। ग्राम पंचायत में सबसे अच्छे तरीकों में से एक बिजली पर निर्भरता को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल केंद्रीय सौर प्रकाश सुविधा की स्थापना है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। घरों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत ने ग्रामीण स्तर पर एक आरओ प्लांट स्थापित किया है। इसके अलावा, गाँव को सुरक्षित, संगठित और खुले में शौच को समाप्त करने के लिए गाँव सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित है। स्वच्छता सुविधा में सुधार के लिए, ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक शौचालय को अपनाया है। यह पाया जाता है कि चेनुष्ठा में प्रत्येक घर में व्यक्तिगत शौचालय हैं। ग्राम पंचायत मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किशोरियों को विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने की पहल कर रही है। चेनुष्ठा ग्राम पंचायत ने स्वच्छता, स्वच्छता और पर्यावरण में सुधार के लिए सार्वजनिक कचरा प्रणाली को अपनाया है। पर्यावरणीय मुद्दों पर गहन जागरूकता अभियान कचरे के निपटान पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया और ग्रामीणों को ठोस और तरल कचरे को अलग करने के तरीकों पर शिक्षित किया गया।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत में बिजली और टेलीफोन बिल जमा करने की भी सुविधा है। इसके अलावा, चेनुष्ठा ग्राम पंचायत में घरों की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आग बुझाने की सुविधा है। ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय में सबसे अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए डिजिटल शिक्षण के माध्यम से शिक्षा के नवीन तरीकों को अपना रही है। ग्राम पंचायत ने विभिन्न योजनाओं से धनराशि को ग्राम पंचायत के भीतर बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए एकत्र किया है। 2016-17 के दौरान, चेनुष्ठा ग्राम पंचायत को 30 लाख रुपये की स्मार्ट ग्राम निधि और टंटा मुक्ति गाँव मोहिम पुरस्कार मिला है। अधिकांश परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत पक्के घरों का निर्माण किया है।

चेनुष्ठा ग्राम पंचायत अच्छे काम करने वाली लोकतांत्रिक पद्धतियों का मामला है। ग्राम पंचायत में जनता ग्राम पंचायत के योजना, कार्य में सहभागी होती है।

**डॉ. रिम्की पाटगिरी,** पीटीएम
**डॉ. प्रत्युस्ना पटनायक,**
सहायक प्रोफेसर
**पंचायती राज केंद्र**

## डीडीयू-जीकेवाई कक्ष, एनआईआरडीपीआर ने किया एसआरएलएम के सीईओ और सीओओ का सम्मेलन

डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से 7 वें)
अन्य गणमान्य व्यक्तियों और सम्मेलन के प्रतिभागियों के साथ

डीडीयू-जीकेवाई के लिए एसआरएलएम के सीईओ और सीओओ के एक सम्मेलन को डीडीयू-जीकेवाई, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा 26-27 अगस्त, 2019 के दौरान प्रगति रिसॉर्ट्स, हैदराबाद में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था रोजगार : 'डीडीयू-जीकेवाई में पदस्थापन चुनौतियां और संभावनाएं'। 'न्यू इंडिया @ 75 के लिए रणनीति में, वर्ष 2022-23 में कौशल प्रदान करना मुख्य लक्ष्यों

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्री संदीप शर्मा, उप-निदेशक, कौशल, एमओआरडी के साथ डीडीयू-जीकेवाई के प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए ।

में से एक है, भारत के कार्यबल के मौजूदा 5.4 प्रतिशत से औपचारिक रूप से कुशल श्रमिकों का अनुपात बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना। जैसा कि राज्यों को इस वित्तीय वर्ष (2019-20) के दौरान हमारे देश के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, डीडीयू-जीकेवाई (दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना), केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

डाटा "युवा निष्क्रियता" में कुछ रुझानों का संकेत देता हैं और बताता हैं कि 15-29 वर्ष की आयु समूह के ग्रामीण भारत में 27 प्रतिशत युवा आबादी एनईईटी (रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं) की श्रेणी में हैं ।
(**स्रोत:** वार्षिक रिपोर्ट: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017-18)

डीडीयू-जीकेवाई ऐसे युवाओं को पर्याप्त रूप से कौशल और रोजगार दे सकता है । एनआईआरडीपीआर ने ' सीईओ सम्मेलन ' की मेजबानी की क्योंकि यह डीडीयू-जीकेवाई में नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों, समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने का सही समय है ।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, ने अपने प्रमुख संबोधन में उद्योग 4.0 के संदर्भ में तेजी से बदलते परिदृश्य में फोरम का ध्यान आकर्षित किया; जिस तरह से युवा अपने विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं और युवाओं को तदनुसार कौशल प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने की निरंतर आवश्यकता है ।

महानिदेशक ने डीडीयू-जीकेवाई के साथ अधिक घनिष्ठता से जुड़ने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों के सीईओ और वरिष्ठ प्रबंधकों का स्वागत किया और उद्योग भागीदारों के रूप में बहु-समर्थन प्रदान किया ।

जिन्हें एनआईआरडीपीआर द्वारा स्किलिंग पद्धति पर जिन प्रशिक्षकों, प्रशिक्षित किया गया और लाइव टिप्पणियों में गुणवत्ता मानकों को पूरा किया गया, उन्हें मान्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया । सम्मेलन के स्थल पर कार्यरत डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों को सम्मेलन के विषय को उभारने के लिए सम्मानित किया गया । डॉ.डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने 'रिटेल स्नेक एंड लैडर' जारी किया, जो डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया गया एक गेम है । यह खेल डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए परस्पर संवाद सीखने को बढ़ावा देने के लिए एनआईआरडीपीआर के प्रशिक्षण और ई-लर्निंग प्रभागों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया । एक संक्षिप्त अवधि के लिए इसे खेलते समय दर्शक खेल में मग्न रहते हैं ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (कौशल), श्री चरणजीत सिंह ने सम्मेलन के दूसरे दिन श्रोताओं को संबोधित किया और टाटा द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों में से एक डीडीयूजीकेवाई में गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने एक कौशल अंतराल अध्ययन के संचालन के महत्व पर प्रकाश डाला और लोगों में सीआरपी की बढ़ती भागीदारी और नियुक्तियों में राज्य कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका के लिए आग्रह किया । उन्होंने जोर दिया कि शीघ्र ही एसएससी के साथ केंद्रित बैठकें आयोजित की जाएंगी । श्री चरणजीत सिंह ने भावी पीआईए और डीडीयू-जीकेवाई उम्मीदवारों के लिए ई-लर्निंग में एनआईआरडीपीआर की नई पहल जारी की ।

डॉ. पार्थ प्रतिमा साहू, एसोसिएट प्रोफेसर, उद्यमशीलता विकास केन्द्र ने कारणों सहित रोजगार चुनौतियों की मात्रात्मक और गुणात्मक आयामों पर तथा ग्रामीण रोजगार परिदृश्य और बड़े श्रम बाजार के संदर्भ में चुनौतियां पर प्रकाश डाला । डॉ. साहू ने सिफारिश की कि लगातार प्रभाव अध्ययन होना चाहिए, स्किलिंग कार्यक्रमों का अभिसरण और डीडीयू-जीकेवाई को बड़े स्किलिंग स्थान पर रखना, और डीडीयू-जीकेवाई को और अधिक सफल बनाने के लिए कुछ कारकों के रूप में शिक्षुता के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए । उन्होंने उभरते क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ।

डीडीयू-जीकेवाई के लिए कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर नैबकॉन्स के प्रबंध निदेशक श्री के. वेंकटेश्वर राव ने प्रकाश डाला । कृषि क्षेत्र में विभिन्न कार्य भूमिकाएँ, जहाँ युवा कुशल हो सकते हैं । उन्होंने खेती के क्षेत्र में निजीकरण की संभावनाओं को इंगित किया और इसका मतलब होगा कि न केवल बढ़ी हुई दक्षता, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए अधिक रोजगार ।

श्री शंकर दत्त कबदल, निदेशक निगरानी और मूल्यांकन और श्री बी.के. त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, नैबकॉन्स ने सीटीएसए के दृष्टिकोण से डीडीयू-जीकेवाई में प्लेसमेंट के संबंध में चुनौतियों को प्रस्तुत किया ।

श्री पद्मनाभ राव, अपर परियोजना निदेशक, डीडीयू-जीकेवाई ने पिछले सीईओ सम्मेलन से अब तक तय की गई दूरी और एनआईआरडीपीआर द्वारा की गई कार्रवाइयों जैसे कि डीडीयू-जीकेवाई के लिए एक आम ईआरपी पद्धति, पिछले साल एसआरएलएम के सीईओ द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रस्तुत किया गया ।

क्षेत्र कौशल परिषदों के सीईओ एवं वरिष्ठ सदस्यों जैसे – ग्रीन जॉब्स, पॉवर, पेन्ट्स एवं कोटिंग्स, कैपिटल गूड्स, ऑटोमेटिव, बीएफएसआई, पर्यटन एवं अतिथ्य सत्कार, प्रबंधन एवं उद्यमशीलता एवं विकलांग व्यक्ति क्षेत्र कौशल परिषद ने विभिन्न मार्गों एवं डीडीयु – जीकेवाई अभ्यर्थी कौशल एवं पदस्थापन के लिए नये अवसरों को प्रस्तुत किया ।

डॉ. एम. श्रीकांत, निदेशक-वित्त और मूल्यांकन ने

डीडीयू-जीकेवाई में मूल्यांकन और वित्त की स्थिति प्रस्तुत की। श्री जी.बी.के. राव ने सम्मेलन के दूसरे दिन उपस्थित लोगों से स्वास्थ्य संबंधी बातचीत की और स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य देने वाले पौधों पर जानकारी साझा की । श्री समीर गोस्वामी, एमआईएस, डीडीयू-जीकेवाई के निदेशक ने कौशल भारत, डीडीयू-जीकेवाई के लिए ईआरपी और राज्यों द्वारा इसके रोल आउट और गोद लेने पर एक प्रस्तुति दी।

श्री भास्कर नटराजन, कार्यक्रम निष्पादन प्रमुख, टाटा स्ट्राइव ने कौशलयुक्त ग्रामीण युवाओं में टाटा स्ट्राइव के द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धतियों को प्रस्तुत किया। केरल के कुदुम्बश्री के कार्यकारी निदेशक श्री हरि किशोर ने केरल में कार्यान्वित डीडीयू-जीकेवाई में अभिसरण और 16 सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक विचार प्रस्तुत किया। इसमें डीडीयूजीकेवाई छात्रों के लिए यूनिफॉर्म सिलाई और कैंटीन में एसएचजी महिलाएं शामिल थीं।

पंचायती राज के एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, डॉ. सी. कतिरेसन ने बेहतर परिणामों के लिए पंचायती राज के साथ डीडीयू-जीकेवाई के अभिसरण अवसरों पर एक प्रस्तुति दी, इस तथ्य को देखते हुए जीपीडीपी में स्किलिंग पर विशेष ध्यान दिया गया । उन्होंने निम्नलिखित को अभिसरण के लिए आगे के रास्ते के रूप में सुझाया:

1. जीपीडीपी और अभिसरण पर पीआईए का उन्मुखीकरण
2. जीपीडीपी के लिए जन योजना अभियान में पीआईए/प्रतिनिधियों की भागीदारी
3. विशेष ग्राम सभा और प्रस्तुति में भागीदारी
4. ग्राम पंचायत स्तर के कार्य समूह / स्थायी समितियों के परामर्श से ग्रामवार कौशल की माँग की तैयारी
5. जीपीडीपी के भाग के रूप में कौशल विकास का एकीकरण सुनिश्चित करना
6. कार्यान्वयन पर ग्राम पंचायत स्थायी समितियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई

राज्यों ने अपनी सर्वोत्तम पद्धतियों को प्रस्तुत किया, जिन्होंने सीईओ को अपनी सहक्रियाओं के निर्माण का अवसर प्रदान किया । पहचान किए गए अंतराल पर चर्चा करने के लिए चार कार्य समूहों का गठन किया गया, डीडीयू-जीकेवाई कार्यान्वयन और एनआईआरडीपीआर और एमओआरडी से आवश्यक समर्थन को मजबूत करने के लिए अगले छह महीनों के लिए पांच साहसिक कदम, जो प्रत्येक समूह द्वारा मंच पर प्रस्तुत किया गया।

संयुक्त सचिव (कौशल) एमओआरडी, श्री चरणजीत सिंह ने अपनी समापन टिप्पणी में, संशोधन की सफलता में योगदान देने वाले कारकों को बढ़ाने के लिए एसआरएलएम, एनआईआरडीपीआर, नैबकॉन्स और एसएससी की आवश्यकता पर जोर दिया।

अपनी समापन टिप्पणी में, एन आई आर डी पी आर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी उद्योग के साथ जुड़ाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों को रोजगार, संवारने और प्रशिक्षण के लिए क्यूपी का संयोजन। "गुणवत्ता, प्रशिक्षुता-आधारित शिक्षा (एनएपीएस) को सुनिश्चित करने के लिए कौशल अंतर विश्लेषण जो विश्वसनीय, गतिशील और समवर्ती है, सीएपीईएक्स भारी नौकरी की भूमिकाओं के लिए सीएसआर का लाभ उठाते हुए, एसएससी और एसआरएलएम के बीच सुचारू डेटा प्रवाह सुनिश्चित करता है," ऐसा उन्होंने कहा।

"एसएससी के साथ क्षेत्र-वार कार्यशाला, उपयुक्त ट्रेडों पर पीआईए को उन्मुख करना, नियोक्ता समूह का विस्तार करना, पीआईए का उल्लेख करना और उसे संभालना अन्य तरीके हैं ।" महानिदेशक ने आगे और काम करने वाले लोगों की संभावनाओं पर विचार करने के लिए मंच को आग्रह किया, जो नीतिगत स्तर के निर्णय ले सकते है, जो वर्तमान संदर्भ में खोज करने लायक है । प्रशिक्षण प्रभाग, डीडीयू-जीकेवाई और कौशल और रोजगार केंद्र, एमओआरडी ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

---

## सीडीसी द्वारा संकट संचार और मीडिया प्रशिक्षण पर कार्यशाला का आयोजन

विकास प्रलेखन और संचार केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने 16 अगस्त 2019 को संस्थान में संकट संचार और मीडिया प्रशिक्षण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का संचालन सुश्री भवानी गिद्दू वीरावल्ली, संस्थापक और सीईओ, फूटप्रिंट ग्लोबल कम्युनिकेशन द्वारा किया गया।

सुश्री भवानी गिद्दू, जनसंपर्क और नीतिपरक मीडिया संबंधों में 27 वर्षों के अनुभव के साथ एक वरिष्ठ संचार पेशेवर हैं, उन्होंने संकट संचार पर एक सत्र संचालित किया।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और अन्य संकाय सदस्यों ने सत्र में भाग लिया। सुश्री भवानी गिद्दू वीरावल्ली ने सत्र का नेतृत्व किया और उनकी सहायता सुश्री मधुलिका वी. नरसिम्हन, सहायक प्रबंधक- विशेष परियोजनाओं, और श्री साईराम राधाकृष्णन, संचार विशेषज्ञ, फूटप्रिंट ग्लोबल कम्युनिकेशन द्वारा की गई।

जिन विषयों पर उन्होंने संपर्क किया उनमें सार्वजनिक संबंध संकट, संभावित संकट ट्रिगर, संकट का जीवन चक्र, प्रतिक्रिया रणनीति, प्रतिक्रिया तंत्र, अधिकृत प्रवक्ता की प्रासंगिकता और संकट की स्थिति में क्या करना और क्या नहीं करना शामिल हैं। वास्तविक जीवन के अनुभवों का हवाला देते हुए, उन्होंने संकट की स्थिति के दौरान मीडिया से प्रश्नों को संभालने के तरीके बताए । व्याख्यान के बाद, उन्होंने प्रतिभागियों को कई कृत्रिम प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया।

मीडिया प्रशिक्षण के सत्र का दूसरा भाग श्री साईराम राधाकृष्णन, संचार विशेषज्ञ, पदचिह्न वैश्विक संचार द्वारा संचालित किया गया । श्री साईराम ने बेहतर मीडिया संबंधों को बनाए रखने के लिए एक संस्थान की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बात की। देश में मीडिया परिदृश्य का अवलोकन करते हुए, उन्होंने उन विषयों के बारे में बात की जो मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं, एक महत्वपूर्ण संदेश के तत्व, प्रमुख संदेशों को संप्रेषित करने के तरीके, मीडिया की संपर्क प्रक्रिया और एक संगठन में मीडिया कक्ष बनाने के महत्व, उन्होंने उन तरीकों के बारे में जानकारी दी जिसमें एक संस्थान मीडिया में खुद को ढाल सकता है।

अपने समापन में, महानिदेशक ने अपने अच्छे काम को बढ़ावा देने और अधिक सीएसआर गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए मीडिया संबंधों के बारे में अवसर का अधिकतम उपयोग करने के लिए संकाय से आग्रह किया। डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, सीडीसी ने कार्यशाला का समन्वय किया।

**- सीडीसी की पहल**

# डॉ. सुरेश बाबू, आईएफपीआरआई भारतीय कृषि में ग्रामीण विकास की चुनौतियों पर व्याख्यान देते हुए

डॉ. सुरेश बाबू, वरिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य और प्रमुख, क्षमता सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, वाशिंगटन एनआईआरडीपीआर में ' भारतीय कृषि में ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ' पर व्याख्यान देते हुए

विकास प्रलेखन एवं संचार केन्द्र (सीडीसी), एनआईआरडीपीआर ने डॉ. सुरेश बाबू, वरिष्ठ अनुसंधान अधिसदस्य और प्रमुख, क्षमता सुदृढ़ीकरण अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, वाशिंगटन ने १९ अगस्त, 2019 को 'भारतीय कृषि में ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ' पर एक व्याख्यान का आयोजन किया।

डॉ. सुरेश बाबू एनआईआरडीपीआर द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका ग्रामीण विकास जर्नल के सलाहकार संपादकीय बोर्ड के सदस्य भी हैं।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीडीसी ने स्वागत भाषण दिया और स्पीकर को दर्शकों से परिचित कराया। श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने उन्हें पुष्पगुच्छ देते हुए व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया।

डॉ. सुरेश बाबू ने कीटनाशक के उपयोग में वृद्धि के कारण कृषि पुनरूद्धार की आवश्यकता पर बल दिया, जो कि किसानों को सब्सिडी के साथ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसमें कई मुद्रा संबंधी निहितार्थ हैं। उन्होंने अशोक गुलाटी की पुस्तक 'भारतीय कृषि में उपदान सिंड्रोम ' को भी उद्धृत किया और सब्सिडी देने में जो पैसा खर्च किया जाता है, उसे ग्रामीण विकास को कम करने के लिए अन्य क्षेत्रों में पंप किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास अनुसंधान के बारे में बात करते हुए, डॉ. सुरेश बाबू ने कहा कि दक्षिण कोरिया शहरीकृत और औद्योगिकी बन गया है, फिर भी समुदाय आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है। दक्षिण कोरिया भी आगामी शोधकर्ताओं को ग्रामीण विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि चीन ने ग्रामीण और शहरी अर्थशास्त्र के विलय का दृष्टिकोण शुरू किया है जिसे रुबोनोमिक्स कहा जाता है। चीन में, ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों की ई-कॉमर्स तक पहुंच है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ ग्रामीण विकास और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय परिदृश्य के बारे में बात करते हुए, डॉ। सुरेश बाबू ने सुझाव दिया कि शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए तेज किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र पर्यावरण पर निर्भर और फलते-फूलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब केंद्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, तो स्थानीय वातावरण पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उल्लेख किया कि कृषि, नीति-निर्माण और प्रशासन को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ जाना चाहिए।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन डॉ. आकांक्षा शुक्ला के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ।

**- सीडीसी की पहल**

# एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण विकास में भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (दाएं से पहली पंक्ति 4 वाँ स्थान),
डॉ. पी. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीगार्ड (बाएं से पहली पंक्ति 4 वाँ स्थान) और
डॉ. एम वी रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीगार्ड (पहली पंक्ति बायें से 3 स्थान) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ

ग्रामीण विकास में भूसंसूचना अनुप्रयोग केन्द्र (सीगार्ड) ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान में जुलाई 09 से 05 अगस्त, 2019 तक-भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन में ग्रामीण विकास पर चार सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) द्वारा प्रायोजित और सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यशाला में नौ देशों के कुल १६ प्रतिभागियों ने भाग लिया अर्थात् , अर्जेंटीना, इथियोपिया, इराक, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे। प्रतिभागियों में अपने संबंधित देशों में विकास प्रशासन, नीति निर्माण और विकास के कार्यक्रम में कार्यरत मध्यम स्तर के और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल है।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, एनआईआरडीपीआर के उप महानिदेशक द्वारा किया गया। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए संसाधनों की योजना, निगरानी और प्रबंधन के लिए विकास में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और सूचना के महत्व पर जोर दिया। अपने उद्घाटन भाषण में, श्रीमती राधिका रस्तोगी ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे संबंधित देशों के विकास में उपयोग के लिए नई तकनीकों और अनुप्रयोगों के बारे में जानने के लिए सक्रिय रूप से भाग लें। पाठ्यक्रम निदेशक ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रशिक्षण विधियों आदि की जानकारी दी।

सभी प्रतिभागियों ने अपने देशों के बारे में प्रस्तुतियां दीं, विशेष रूप से रुपरेखा, ग्रामीण विकास पहल, नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों, नवाचारों, चुनौतियों और विभिन्न क्षेत्रों में भू-सूचना के उपयोग पर, इसके बाद चर्चा हुई। इन प्रस्तुतियों ने प्रतिभागियों को विभिन्न देशों के बारे में जानने का मौका दिया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) के पाठ्यक्रम टीम के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा कक्षा सत्र को संचालित किया गया, जो भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्यरत है। भारत के अभिनव और सर्वोत्तम पद्धतियों पर प्रख्यात वैज्ञानिकों (एनआरएससी / आईएसआरओ) द्वारा विषयों को कवर किया गया। कार्यक्रम के भाग के रूप में, प्रतिभागियों को संस्थान के निकट अनुसंधान केंद्रों की जानकारी दी गई जैसे - अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबंधी संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज (आईएनसीओआईएस), हैदराबाद ताकि व्यक्ति में व्यावहारिक अनुभव को समझ सके।

ग्रामीण विकास की दिशा में स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और प्रौद्योगिकी प्रसार का पता लगाने के लिए प्रतिभागियों को एक सप्ताह के अध्ययन दौरे के लिए मैसूरु और बेंगलुरु ले जाया गया। पहले दिन, प्रतिभागियों ने एएनएसएसआईआरडी, मैसूरु में एसएटीसीओएम सुविधा का दौरा किया। एएनएसएसआईआरडी के संकाय ने ग्राम पंचायतों के लिए इंटरैक्टिव प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सैटकॉम-उपग्रह-आधारित प्रौद्योगिकियों के उपयोग का प्रदर्शन किया। बाद में, उन्होंने मैसूरु में कर्नाटक राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र का दौरा किया तथा बेंगलुरु में, सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय मृदा विज्ञान और भूमि-उपयोग योजना (एनबीएसएस एवं एलयूपी), क्षेत्रीय केंद्र, कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र (केएसएनडीएमसी) कर्नाटक राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, बेंगलुरु में संकाय के साथ बातचीत की।

इस सत्र की अध्यक्षता श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा की गई। उन्होंने मुख्य अतिथि डॉ. टी. वी. नागेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार, नई दिल्ली का स्वागत किया, जिन्होंने समापन भाषण दिया। पाठ्यक्रम निदेशक ने डॉ. टी. वी. नागेंद्र प्रसाद को पाठ्यक्रम रिपोर्ट प्रस्तुत की। डॉ. टी. वी. नागेंद्र प्रसाद ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि सदस्य देशों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कई समस्याओं के समाधान के लिए भू-सूचना विज्ञान जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने भविष्य के ज्ञान के बंटवारे के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में एलुमनी नेटवर्किंग और आईटीईसी कार्यक्रमों के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

सभी प्रतिभागियों ने महसूस किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके राष्ट्र स्तरीय योजना तैयार करने और विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए उपयोगी था। पाठ्यक्रम टीम में डॉ. पी. केशव राव, एसोसिएट प्रोफेसर और अध्यक्ष, डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, इंजीनियर एच. के. सोलंकी, सहायक प्रोफेसर (सीनियर) और डॉ. एन. एस. प्रसाद, सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड शामिल थे।

# जे-पाल के सहयोग से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव आकलन पर क्षमता निर्माण कार्यशाला

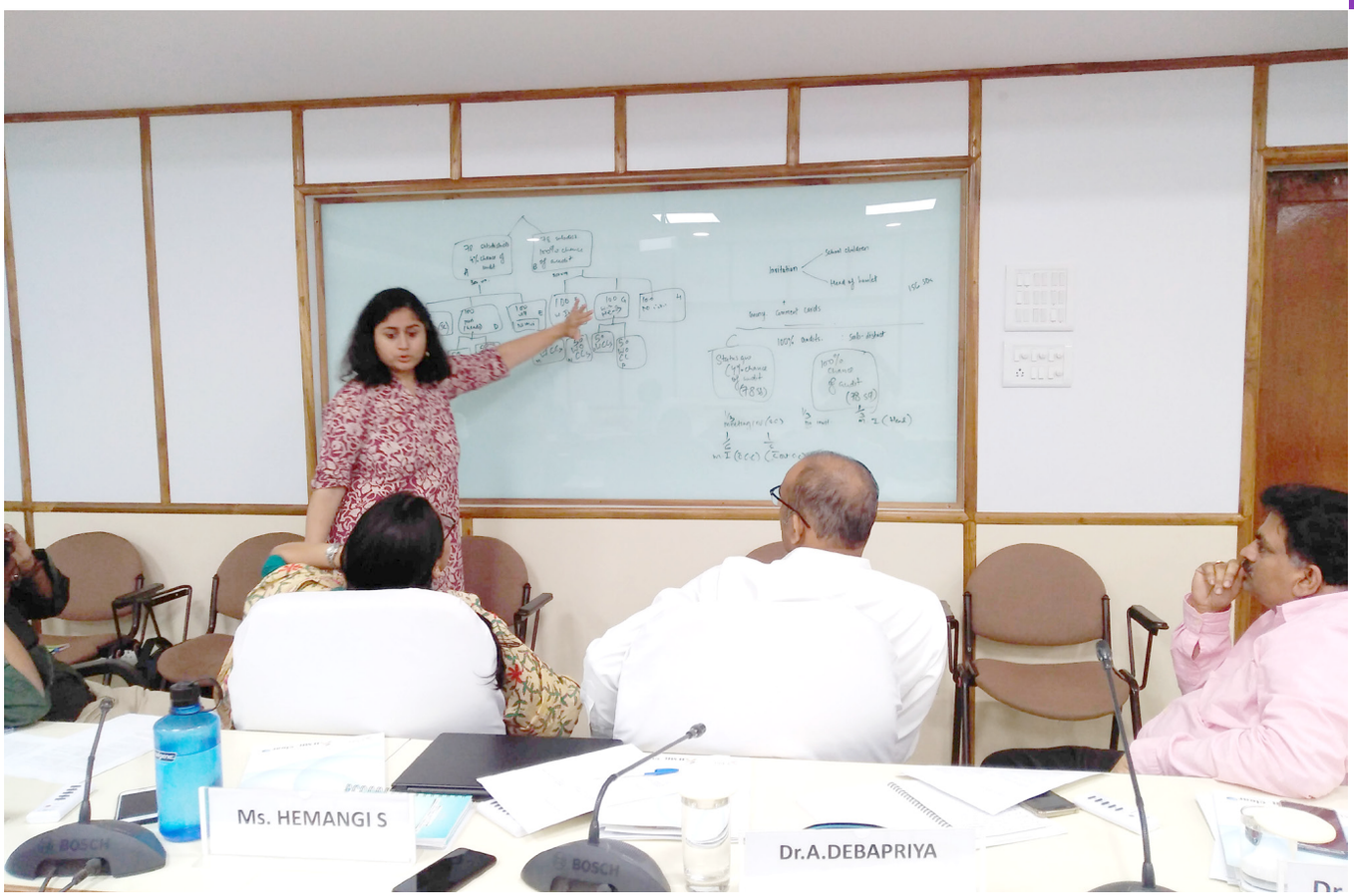


सुश्री सोहिनी मुखर्जी कार्यशाला के दौरान विकास कार्यक्रमों के प्रभाव आकलन पर एक सत्र को संचालित करती हुई

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब (जे-पाल) के साथ मिलकर एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में 27 से 29 अगस्त, 2019 के दौरान 'विकास कार्यक्रमों के प्रभाव आकलन' पर एक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण-कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य एनआईआरडीपीआर और एसआईआरडी के संकाय को उन्नत ज्ञान के साथ सुसज्जित करना, प्रभावी ढंग से विकास के हस्तक्षेप के प्रभाव मूल्यांकन पर जोर देने के साथ निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कौशल प्रदान करना था।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया और समन्वयन डॉ. जी. वी. राजू, प्रोफेसर और अध्यक्ष, योजना, निगरानी और मूल्यांकन, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया।

पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में शामिल है -

(i) 'परिवर्तन का प्रभावी सिद्धांत' डिजाइन करने का ज्ञान बढ़ाना और निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसका महत्व

(ii) विकास संकेतक और मापन सिद्धांत पर ज्ञान का विस्तार करना

(iii) यादृच्छिक मूल्यांकन पर ध्यान देने के साथ विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन विधियों की गुण-दोषों को उजागर करना

(i v ) अनियमित मूल्यांकन के डिजाइन और संचालन के सिद्धांतों और चरणों को समझना

(v ) शक्ति, नमूना आकार की गणना और यादृच्छिक मूल्यांकन के बाद डिजाइन चुनौतियों को समझना

(vi) निर्णय लेने में मौजूदा यादृच्छिक मूल्यांकन से विश्वसनीय सबूतों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के तरीके को समझना।

एनआईआरडीपीआर और एसआईआरडी के विभिन्न केंद्रों से कुल १९ संकायों ने सुश्री सोहिनी मुखर्जी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जे-पाल पाठ्यक्रम दल के साथ तीन दिवसीय लंबे पाठ्यक्रम में भाग लिया।

कार्यक्रम के पहले दिन सामान्य रूप से परिवर्तन के सिद्धांत (टीओसी) पर जोर देने के साथ निगरानी और मूल्यांकन तकनीकों की मूल बातें शामिल की गईं, साथ ही कार्यक्रम के लिए संकेतक डिजाइन किए गए हैं। विभिन्न मूल्यांकन विधियों, यादृच्छिक उपचार की तकनीक, नमूना आकार और शक्ति गणना के साथ कई उपचार हथियारों का उपयोग कर यादृच्छिक डिजाइन दूसरे दिन सत्र की सामग्री थी। पाठ्यक्रम के तीसरे और अंतिम दिन, किसी कार्यक्रम के वास्तविक प्रभाव को मापने के लिए विभिन्न परिदृश्यों के दौरान खतरों और इसके विश्लेषण जैसे विषयों पर निगरानी तकनीकों के माध्यम से प्रमाणिक प्रगति का उपयोग करने पर चर्चा की गई। प्रत्येक दिन, सैद्धांतिक सत्र के बाद व्यावहारिक अभिविन्यास के सत्र के बाद, केस विधि तकनीक का उपयोग करके कुछ प्रासंगिक केस स्टडीज को कवर किया गया। कुल मिलाकर, जे-पाल के साथ सहयोगी कार्यक्रम ने एक कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने में आरसीटी (यादृच्छिक नियन्त्रण ट्रायल) की तकनीक का उपयोग करते हुए विशेष रूप से निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों पर संकाय को काफी फायदा पहुंचाया है।

# मोबाइल फिल्म निर्माण पर तीन दिवसीय कार्यशाला ने प्रशस्त किया नवोदित फिल्म निर्माताओं के लिए अधिक विकल्पों के अवसर

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (दाईं ओर से दूसरे), प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए। डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से तीसरे) और श्री शशिभूषण, वित्तीय सलाहकार (बाएं से दूसरे), श्री सुनील प्रभाकर, स्त्रोत व्यक्ति (बाएं से प्रथम) और डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस और डीई एवं अध्यक्ष, सीडीसी (दाएं से प्रथम) भी देखे जाते हैं

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विज्ञान प्रसार इकाई के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने 23 से 25 अगस्त 2019 तक मोबाइल फिल्म निर्माण पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

२३ अगस्त २०१९ को उद्घाटन सत्र में डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और अन्य अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण विकास में एक प्रभावी माध्यम के रूप में फिल्म निर्माण के महत्व के बारे में बताया। "आत्मकथाओं को देखने से, हमें महान विद्वानों के जीवन के बारे में एक प्रेरणा विचार मिलता है और ये फिल्में हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। भारतीय राज्यों ने हर साल बनने वाली फिल्मों की संख्या के मामले में हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है। जीवन में कुछ घटनाएँ होती हैं जिन्हें हम फिर से याद नहीं कर सकते हैं, ऐसे उदाहरणों को फ़िल्माया जाना चाहिए। प्रतिभागियों को इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए" उन्होंने कहा।

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने कार्यशाला के स्त्रोत व्यक्तियों श्री सुनील प्रभाकर और श्री रितेश टकसंडे का स्वागत किया। उन्होंने टिप्पणी की कि लोगों को जीवन में हमेशा रचनात्मक पहलू रखना चाहिए। "उन्हें अन्य व्यवसायों में अनुभव प्राप्त करना चाहिए। फिल्म निर्माण एक ऐसी गतिविधि है," उन्होंने कहा और छात्रों को इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उनसे फिल्मों के माध्यम से ग्रामीण भारत में निम्न स्तर पर प्रेरक कहानियों को रिकॉर्ड करने का भी आग्रह किया।

भारत में 560 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से अधिकांश गांवों में रहते हैं और अब उनके पास किफायती मोबाइल डेटा तक पहुंच है। इस संदर्भ में, ज्ञान, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑडियो-विज़ुअल सामग्री के उपयोग को बढ़ाना सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए एक स्थायी और स्मार्ट माध्यम हो सकता है, उन्होंने कहा।

संयुक्त राष्ट्र के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करने वाले तकनीकी प्रशिक्षक श्री सुनील प्रभाकर ने कहा कि 97 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ता ऑनलाइन वीडियो देखते हैं। यह हमारे सामने प्रस्तुत अवसर की पुष्टि करता है, लोगों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिध्वनित होने वाली शक्तिशाली फिल्मों के माध्यम से जनता तक पहुंचना है।

सभा को संबोधित करते हुए, पुणे के एक फिल्म निर्माता श्री रितेश टकसंडे ने विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने वाली फिल्में बनाने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. आर्यश्री देबप्रिया, एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर अध्ययन एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्र (सीपीजीएस एवं डीई) ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान प्रसार और एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक के लिए इस तरह का एक मंच बनाने की सराहना की।

उद्घाटन के बाद वाले सत्र और अगले दो दिनों में संसाधन व्यक्तियों - श्री निमिष कपूर, वैज्ञानिक ई, विज्ञान प्रसार और श्री संतोष पांडे, वरिष्ठ निर्माता, ईटीवी भारत, श्री सुनील प्रभाकर, और श्री रितेश टकसंडे ने फिल्म निर्माण के विभिन्न तत्वों का परिचय दिया।

छात्रों को फिल्म निर्माण की मूल बातें सिखाई गईं जैसे कि कैमरा शॉट्स, कहानी दृष्टिकोण, पटकथा लेखन और फिल्म संपादन। कार्यशाला के दौरान उन्हें स्मार्टफोन का उपयोग करके पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और बाद के उत्पादन से निपटने के लिए प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया।

उनके द्वारा कवर किए गए सत्रों में विज्ञान संचार शामिल है: मोबाइल विज्ञान फिल्म निर्माण के लिए

क्यों और कैसे, फिल्मांकन, आईफोन और एंड्रॉइड कैमरा सेटिंग्स के लिए फोन तैयार करें; देशी कैमरा ऐप -फोकस और एक्सपोज़र का उपयोग करना, स्मार्ट फोन वीडियो के लिए टिप्स, कॉम्प्लेक्शन एलिमेंट और बेसिक्स ऑफ़ विडियोग्राफी, सीन, शॉट्स विद कैमरा एंड शूटिंग, स्क्रिप्ट विद साइंस फ़िल्में: स्क्रिप्ट के प्रत्येक शब्द के लिए दृश्यों के बारे में सोचें, समूहों में प्रतिभागियों द्वारा प्रयोगात्मक फिल्म की शूटिंग, तीसरे पक्ष के कैमरा ऐप: डिजिटल वीडियो बेसिक्स, थर्ड पार्टी एप्स, अन्य एप्स में एडवांस कंट्रोल, वीडियो स्टेबिलिटी - गियर के साथ और बिना, ऑडियो गियर, लेंस और लाइटिंग से परिचय, वीडियो प्रोडक्शन से पहले और शूटिंग के दौरान, वीडियो प्रोडक्शन नॉर्म्स, स्मार्ट के साथ बेसिक वीडियो एडिटिंग फोन, परिचित वीडियो संपादन ऐप - फ़िल्मोरा गो, व्लॉगिट, आईमूवी, कीनेमास्टर, लुमा फ्यूजन; क्लिप को व्यवस्थित और ट्रिम करना; फ़िल्मोरा गो / क्रिक / व्लॉगिट - ट्रिमिंग, क्लिप का आयोजन, पृष्ठभूमि संगीत जोड़ना, कथन पर आवाज रिकॉर्ड करना, संक्रमण प्रभाव जोड़ना, ओवरले और प्रभाव का उपयोग करना, शीर्षक बनाना, वीडियो उत्पादन के लिए नए युग के क्लाउड-आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करना, शॉट्स की समीक्षा करना, कट और शॉट फ्लो आदि को समझने के लिए संपादन तालिका।

दूसरे दिन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विज्ञान फिल्में: 'घरत: रिवाइवल ऑफ वॉटरमिल्स' और नौला: वॉटर टेम्पल ऑफ हिमालय', और आईआईएसएफ पुरस्कार विजेता फिल्म 'चिल्ली' प्रदर्शित की गई और स्रोत व्यक्तियों ने विभिन्न तकनीकों पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा की।

अंतिम दिन, प्रतिभागियों को पहले सत्रों में प्राप्त प्रशिक्षण का उपयोग करके लघु फिल्मों के निर्माण के लिए समूहों में विभाजित किया गया।

२५ अगस्त २०१९ को आयोजित मोबाइल फिल्म निर्माण कार्यशाला में, डॉ। आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस और डीई और अध्यक्ष, सीडीसी ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

उन्होंने आगे स्रोत व्यक्तियों श्री संतोष पांडे, श्री रितेश और श्री सुनील प्रभाकर से अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए कहा।

श्री संतोष पांडे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों में सृजनात्मकता का संचार कर सकता है । अपना ध्यान, प्रतिबद्धता और ईमानदारी के लिए प्रतिभागियों की प्रशंसा करते हुए, उन्होंने कहा कि वे प्रभावी संचार बनाने में बहुत कुछ सीख सकते हैं।

"आपको अपने विचारों को व्यवस्थित और एक माध्यम पर लाना होगा । सुनिश्चित करें कि संदेश प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया गया है । अब, आप माध्यम की शक्ति को समझ गए हैं और आपको इसे अपने चयनित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अगले स्तर पर ले जाना है" उन्होंने कहा।

श्री सुनील प्रभाकर ने कहा कि इस आयोजन से छात्रों और संकाय को विजुअल का उपयोग करके अपने संदेशों को संप्रेषित करने की तकनीक सीखने में मदद मिली है । इसके अलावा, वह उन्हें ग्रामीण जनता तक सूचना पहुँचाने की कला में महारत हासिल करना चाहता है।

पुरस्कार विजेता लघु फिल्म को याद करते हुए, 'कलाकार' श्री रितेश ने बताया कि कई लोग ग्रामीण और आदिवासी आबादी द्वारा अनुभव किए गए बहु आयामी मुद्दों से अनभिज्ञ हैं । वह चाहते थे कि प्रतिभागी अपनी तकनीक के माध्यम से अपनी दशा पर प्रकाश डालें और अपने कौशल को तराशने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता पर जोर दें।

इसके बाद महिला सशक्तीकरण, एनआईआरडीपीआर की भूमिका आदि विषयों पर लघु फिल्मों की समूह-वार स्क्रीनिंग की गई, ताकि व्याख्यान सत्रों को व्यावहारिक उत्पादन में आत्मसात करने की डिग्री का आकलन किया जा सके। समूह के सदस्यों ने अपने अनुभव को साझा किया और विशेषज्ञों ने कमियों और क्षेत्रों की ओर इशारा किया, जिनमें सुधार की आवश्यकता है । उन्होंने फिल्मों का त्वरित विश्लेषण भी किया और तकनीकी पहलुओं जैसे कि पटकथा, उप-शीर्षक, सुव्यवस्थित विचारों आदि पर टिप्पणी की।

गतिविधियों को संक्षिप्त करते हुए, डॉ. ए. देबप्रिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस और डीई ने कहा कि कार्यशाला ने उन्हें छात्रों के सृजनात्मक पक्ष की खोज करने का अवसर दिया, ग्रामीण विकास व्यवसायी के रुप में यह कहते हुए कि सीखने से उन्हें अपने संदेशों को समाज के साथ साझा करने में काफी मदद मिलेगी।

उन्होंने विज्ञान प्रसार द्वारा निभाई गई भूमिका और एनआईआरडीपीआर के साथ उनके निरंतर सहयोग का भी उल्लेख किया। छात्रों के कौशल को पोषित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर देते हुए, उन्होंने विज्ञान प्रसार, विशेष रूप से श्री निमिष कपूर का आभार व्यक्त किया।

इसके अलावा, डॉ. ए. देबप्रिया और डॉ. आकांक्षा शुक्ला ने स्रोत व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया । यह कार्यक्रम स्रोत व्यक्तियों द्वारा अतिथियों को प्रमाण पत्र वितरित करने के साथ संपन्न हुआ। डॉ. आकांक्षा शुक्ला द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस और डीई एवं अध्यक्ष, विकास प्रलेखन और संचार केंद्र ने कार्यशाला का समन्वय किया।

## आईसीटी अनुप्रयोग और ई-शासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्री जी. वी. सत्य नारायण, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सीआईसीटी (पहली पंक्ति दाएं से 5 वें) और डॉ. पद्मजा, डीजीएम, एनआईएसजी (पहली पंक्ति दाएं से 4 थे) प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीआईसीटी) ने एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में 19-23 अगस्त, 2019 के दौरान "आईसीटी अनुप्रयोग और ई-शासन" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जिला परिषद / जिला पंचायतों (जिला परिषद्), एसआईआरडी, ईटीसी, डीआरडीए, कृषि, पशु संसाधन, शिक्षा (एसएसए) और जल संरक्षण विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले लक्षित ग्राहकों के तीस अधिकारी देश भर के १२ राज्यों से आते हैं, अर्थात् कार्यक्रम में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड ने भाग लिया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जिला परिषद्, डीआरडीए, एसआईआरडी / ईटीसी और लाइन विभागों जैसे कृषि, पशु संसाधन, शिक्षा (समग्र शिक्षा), स्वास्थ्य मिशन (एनआइएचएम), जल संरक्षण, आदि के कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाना हैं, विशेषकर ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-शासन, मोबाइल शासन, शासन के लिए भूसंसूचना, डिजिटल इंडिया में आईसीटी और इसके अनुप्रयोगों की क्षमता और सूचना प्रणाली के विकास में कौशल प्रदान करना था।

डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान, महानिदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम लक्ष्य आईसीटी अनुप्रयोगों का उपयोग इस तरह से होना चाहिए कि वे ग्रामीण गरीबों को सेवा वितरण में सुधार करें। उन्होंने यह भी कहा कि आईसीटी अनुप्रयोगों को निम्न स्तर पर पहुंचना चाहिए और उनके लाभ के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब भी विकास के लिए नए आईसीटी अनुप्रयोगों का प्रयास किया जाता है, तो मौजूदा अनुप्रयोगों के पहिया को फिर से स्थापित करने के बजाय आवश्यक अनुकूलन के साथ प्रतिकृति के लिए खोजा जाना चाहिए जो समय सहित बहुत सारे संसाधनों को बचाएगा।

सूचना प्रणाली विकास, ई-शासन, ई-लर्निंग, डिजिटल इंडिया, भूसंसूचना से संबंधित विषयों के अलावा, आईसीटी और ई-शासन की क्षमता को बेहतर जानकारी प्रदान करना । स्वास्थ्य में आईसीटी अनुप्रयोग जैसे कि केयर फाउंडेशन हैदराबाद द्वारा टेलीमेडिसिन, सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और वायरलेस सेंसर नेटवर्क (डब्ल्युएसएन) की भूमिका, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में आईसीटी, पंचायत एंटरप्राइज सूट (पीईएस) और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम के दौरान भी चर्चा की गई।

कार्यक्रम के भाग के रूप में सेंटर फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सीडीएसी) की यात्रा की व्यवस्था की गई ताकि कृषि और स्वास्थ्य सेवा में साइबर सुरक्षा, आईओटी और इसके अनुप्रयोगों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके।

श्री समीर गोस्वामी, सलाहकार (सीआईसीटी) ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

सभी प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और सत्रों को रोचक बना दिया। कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई और प्रतिभागियों ने बताया कि इस तरह के कई कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता है। कार्यक्रम का समन्वयन श्री जी.वी. सत्य नारायण, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीटी) द्वारा किया गया।

---

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)


**राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान**
**ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार**
**राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030**

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

**डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी,** आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
**श्रीमती राधिका रस्तोगी,** आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

**सहायक संपादक:** कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा
एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

**हिन्दी संपादन:**
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन